वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ेगा बजट

अभी 15 विभागों की 130 योजनाएं शामिल हैं ओटीडी में, नए बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित

राज्य ब्यूरो, जागरण• लखनऊ: राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2029-30 तक वन ट्रिलियन डालर (ओटीडी) तक पहुंचाने के लिए 11 तारीख को पेश किए जाने वाले राज्य बजट में कई नई परियोजनाएं भी शामिल की जा सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए 50 से 60 हजार करोड़ रुपये तक बजट आवंटन होने का अनुमान है। नियोजन विभाग ने नई परियोजनाओं का ब्योरा सरकार को दिया है।

सरकार ने अगले पांच वर्ष में राज्य के विकास दर को 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। विकास दर को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए सरकार बजट में कई नए प्रविधान कर सकती है। चालू वित्तीय वर्ष में 15 विभागों की 130 से अधिक योजनाएं ओटीडी में शामिल हैं। सबसे अधिक 36

20 प्रतिशत तक राज्य की विकास दर अगले पांच वर्ष में ले जाने का लक्ष्य

योजनाएं भारी व मध्यम उद्योगों से जुड़ी हैं। 16 योजनाएं कृषि, 15 योजनाएं पर्यटन, 13 योजनाएं आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के साथ ही 10-10 योजनाएं पशुधन और लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग से हैं। इन सभी योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 47,918 करोड़ रुपये से कार्य कराए जा रहे हैं।

नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार कहते हैं कि वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के साथ ही आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ओटीडी के लक्ष्य को पाने के लिए वर्ष 2026-27 के बजट के लिए कई नए प्रविधान प्रस्तावित किए गए हैं।

वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को ओटीडी तक पहुंचाने के लिए विकसित यूपी के विजन डाक्यूमेन्ट में लघु अवधि की कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। वर्ष 2029-30 तक कृषि क्षेत्र में सिर्फ उत्पादन में ही नहीं उत्पादकता व निर्यात में भी राज्य को अग्रणी बनाने का लक्ष्य लिया गया है। आइटी क्षेत्र में लखनऊ व कानपुर को एआइ सिटी, एनसीआर-लखनऊ-नोएडा को जीसीसी हब, नए यूनिकार्न स्टार्टअप तथा प्रत्येक मंडल में इंक्यूबेटर सेंटर का विकास करना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा इसरो के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान के लिए सैटेलाइट लांचिंग का प्रयास करने के साथ ही सेमीकंडक्टर व ईवी बैटरी निर्माण में देश में अग्रणी बनने का लक्ष्य शामिल है। वर्ष 2029-30 तक औद्योगिक विकास, पर्यटन, नगर विकास, अवस्थापना विकास, संतुलित विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं कौशल विकास तथा सुरक्षा व सुशासन के क्षेत्र में भी वर्ष 2029-30 तक के लिए कई अहम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2026-27 के बजट से इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सरकार सेक्टरवार अच्छा-खासा पैसा दे सकती है।

MAGZTER